International Journal of Advanced Education and Research
www.multidisciplinaryjournals.net
ISSN: 2455-5746
Received: 13-04-2023, Accepted: 28-04-2023, Published: 13-05-2023
Volume 8, Issue 2, 2023, Page No. 13-17

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की लाभदायकता पर गैर निष्पादित सम्पत्तियों के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

वर्षा रत्नपारखे[1], डॉ. संजीव गुप्ता[2]
[1] शोधार्थी, वाणिज्य संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत
[2] प्राध्यापक, वाणिज्य संकाय, श्यामलाल पाण्डवीय शा. स्ना. महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
गैर निष्पादित सम्पत्ति, वह सम्पत्ति है जो फर्म के लिये राजस्व उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की लाभदायकतापर गैर निष्पादित सम्पत्तियों के प्रभाव के अध्ययन पर केन्द्रित है। जो कि देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सन् 2009–10 से 2019–20 तक के वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गैर निष्पादित सम्पत्तियाँ, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यह इसके तरलता संतुलन को गिरावट की ओर ले जाती हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि विभिन्न वर्षो में एन.पी.ए. के स्तर में उतार चढाव के कारण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की लाभदायकता भी प्रभावित होती है। जिससे उसकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

मूल शब्दः गैर निष्पादित सम्पत्ति, लाभदायकता, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली बैंक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.58ः है इसलिये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को सरकारी बैंक भी कहा जाता है।वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भारत की सबसे बडी और सबसे पुरानी बैंक है। इस बैंक का मुख्यालय मुम्बई (महाराष्ट्र) में है। इस बैंक में लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। एस.बी.आई.के. पास 31 देशों में 190 विदेशी कार्यालय हैं। एस.बी.आई ऐसा पहला बैंक है जिसकी शाखाएं चीन में भी है। 2017 में, दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनियों की ''फॉर्च्यून ग्लोबल 500'' की सूची में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 217 वे स्थान पर थी।

गैर निष्पादित सम्पत्ति

किसी भी बैंक के लिये, बैंक द्वारा ग्राहक को दिये गये ऋण को बैंक की सम्पत्ति के रूप में माना जाता है, इसलिये यदि किसी ऋण की मूल राशि या ब्याज या दोनों ही ऋण दाता अर्थात बैंक को वापस प्राप्त नहीं हो पाते है तो उसे गैर निष्पादित सम्पत्ति के रूप में माना जाता है। गैर निष्पादित सम्पत्तियों की उपस्थिति, निजी क्षेत्र की बैंको की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंको में अधिक पाई जाती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में वसूली की नीतियां निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक उदार है। गैर निष्पादित सम्पत्तियां दो प्रकार की होती हैं सकल एवं शुद्ध। सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति का तात्पर्य बैंक की सभी गैर निष्पादित सम्पत्तियों के कुल योग से है जबकि शुद्ध गैर निष्पादित सम्पत्ति कुल डूबत ऋणों में से किसी भी प्रकार के प्रावधान को घटाने के बाद प्राप्त गैर निष्पादित सम्पत्ति से है। प्रत्येक बैंक गैर निष्पादित सम्पत्ति की स्थिति से बचने के लिये विभिन्न कदम उठाते हैं इसके बाद भी यदि गैर निष्पादित सम्पत्ति की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी राशि वसूल करने के लिये बैंक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके लिये प्रत्येक बैंक में एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (ऋण वसूली अधिकरण) स्थापित किया जाता है। जिसका काम गैर निष्पादित सम्पत्ति की वसूली पर नजर रखना और देय राशि की वसूली करना है।

सम्पत्तियों का वर्गीकरण – रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंको कों, सम्पत्तियों के प्रदर्शन के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहिये। सम्पत्तियों को चार प्रमुख वर्गो में विभाजित किया जा सकता हैः–

1. मानक सम्पत्ति –ऐसी सम्पत्तियां जो बैंको के लिये नियमित रूप से आय उत्पन्न करती हैं। मानक सम्पत्ति कहलाती हैं।
2. उपमानक सम्पत्ति –वे सभी सम्पत्तियां (ऋण एवं अंग्रिम) जिन्हें 12 महीने की अवधि के लिये गैर निष्पादित सम्पत्ति माना जाता है, उन्हें उपमानक सम्पत्ति माना जाता है।
3. संदिग्ध सम्पत्तियां–वे सभी सम्पत्तियां (ऋण एवं अंग्रिम) जिन्हें 12 महीने से अधिक की अवधि के लिये गैर निष्पादित माना जाता है, उन्हें संदिग्ध सम्पत्तियां कहा जाता है।
4. हानि सम्पत्ति –वे सभी सम्पत्तियां जो वसूल नहीं की जा सकती है, उन्हें हानि की सम्पत्ति कहा जाता है।
5. किसी भी बैंक में कोई भी सम्पत्ति निम्नलिखित कारणों से गैर निष्पादित सम्पत्ति बन जाती है।
6. जब कोई ऋणी किसी विशेष कार्य के लिये बैंक से ऋण लेता है और वह कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाता तो परिणामस्वरूप ऋणी बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाता और यह राशि गैर निष्पादित सम्पत्ति बन जाती है।
7. जब ऋणी किसी व्यवसाय के लिये बैंक से ऋण लेता है और वह उस व्यवसाय में असफल हो जाता है। जिसके कारण वह बैंक का ऋण वापस नहीं कर पाता है।
8. जब कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके बैंक से ऋण ले लेता है और फिर जानबूझकर उसे बैंक को वापस नहीं लौटाता है।
9. बैंको की ओर से की गई गलतियों के कारण भी सम्पत्ति गैर निष्पादित सम्पत्ति बन जाती है।

शोध साहित्य की समीक्षा

बेनर्जी बी.और दान, ए.के. (2006) ने अपने शोध में पाया कि गैर निष्पादित सम्पत्ति सार्वजनिक क्षेत्रों के लिये एक समस्या मूलक क्षेत्र है जिस पर सार्वजनिक बैंकों को अपनी प्रबंध क्षमता और लाभदायकता में सुधार करने हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि सार्वजनिक बैंकों के एन. पी.ए. बहुत तेजी से बढ़ रहे है। इस बढ़ती हुई गैर निष्पादित सम्पत्तियों ने देश की अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाया है। सर्वप्रथम सरकार को समय–समय पर बजटीय प्रावधानों के साथ छूट देना पड़ती है जिसे अंत में करदाता को सहन करना पड़ता है। दूसरे यदि उधार ली गई धनराशि का उचित उपयोग नहीं किया जाता है तो सम्पत्ति के निर्माण को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था का विकास खतरे में आ जाता है। सार्वजनिक बैंकों के एन.पी.ए. को नियंत्रित करने के लिये शोध पत्र लेखक ने कई सुझाव भी दिये है[1]।

जत्ना रेणु (2009) ने समीक्षा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एन.पी.ए. बढ़ने का मूल कारण बैंकों की खराब स्थिति है। इस खराब स्थिति के कारण नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई जिसने एन.पी.ए. को सार्वजनिक क्षेत्र की बैकों में खराब स्थिति का जिम्मेदार ठहराया। रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार 1999 में यह कहा गया था कि एन.पी.ए. में कमी को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में माना जाना चाहिये[2]।

रावल मनीष भास्कर भाई (2014) ने ''एन एनेलेटिकल स्टडी ऑफ नॉन परफार्मिंग असेट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इण्डिया'' विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और अपने शोध में बताया कि एन.पी.ए. बैंकों की लाभदायकता पर प्रभाव ड़ालता है लेकिन एन.पी.ए. एक मात्र ऐसा कारक नहीं है जो बैंकों की लाभदायकता को प्रभावित करता है। कई अन्य कारक भी हैं जो इसे प्रभावित कर सकते है। शोधकर्ता ने अपने शोध में यह भी पाया कि बैंक एन.पी.ए. को नियंत्रित करने के लिये नीतियां तो तैयार करते है। लेकिन इन नीतियों को गंभीरता से लागू नहीं किया जाता है[3]।

अजीत कुमार (2016) ने ''द इम्पेक्ट ऑफ एन.पी.एज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पटना बिहार'' विषय पर अपने शोध ग्रंथ में बताया कि बढ़ते एन.पी.ए. के कई कारण है उनमें सबसे गंभीर है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्टर्स जानबूझकर लोन की राशि वापस नहीं करते हैं। ज्यादातर मामलों में बैंक कर्मचारी भी शामिल होते है। इस संबंध में बैंको को चूककर्ताओं और शामिल कर्मचारी दोनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिये। कार्यो के प्रति जबावदेही निश्चित करने का यही सही समय है। ईमानदार कर्मचारी को उसके अच्छे कार्य के लिये सम्मानित किया जाना चाहिये। शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन के द्वारा प्रभावी वसूली प्रणाली के साथ उचित क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और रिर्पोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैंको को कुशल और प्रभावी बनाने के लिये सुझाव दिये[4]।

सिंह राजबहादुर विवेक (2016) ने अपने शोध पत्र में बताया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र गैर निष्पादित सम्पत्तियों के बढ़ने की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। एन.पी.ए. की वृद्धि का बैंकों की लाभदायकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह समस्या न केवल बैंकों को प्रभावित करती है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभवित करती है[5]।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में गैर निष्पादित सम्पत्तियों में वृद्धि के लिये जिम्मेदार कारक–

1. बैंक के द्वारा उधारकर्ताओं की साख का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता और सिर्फ परियोजना के सफल समापन की उम्मीद में ऋण दे दिया जाता है तो ऐसे ऋणों के गैर निष्पादित सम्पत्ति बनने की अधिक सम्भावना रहती है।
2. बैंक, ऋण या अग्रिम प्रदान करते समय बाजार योग्यता, स्वीकार्यता एवं सुरक्षा आदि सिद्धांतों पर विचार नहीं करते हें जो बाद में उनके लिये घातक सिद्ध हो सकता है।
3. बैंक के कर्मचारियें को एन.पी.ए. की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के विषय में उचित ज्ञान और प्रशिक्षण न होने के कारण एन.पी.ए. में वृद्धि होती चली जाती है।
4. ऐसे उधारकर्ता जिनके पास ऋण को चुकाने हेतु पर्याप्त धन होता है लेकिन वे जानबूझकर बैंक को ऋण का पैसा वापस नहीं करते हैं।
5. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपने ऋणों को जल्दी और कुशलता से वसूलने में मदद करने के लिये भारत सरकार ने देश भर में ऋण वसूली अधिकरण (Debt Recovery Tribunals) की स्थापना की है लेकिन उनकी लापरवाही और निष्क्रियता के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित है।
6. कई बार सरकारी एजेसियां प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कुछ लोगों को ऋण देने के लिये बैंकों पर दबाव डालती है। राजनीतिक प्रभाव के तहत जो ऋण दिये जाते हैं उन्हें पुनः प्राप्त करना बैंकों के लिये कठिन हो जाता है। जो अंत में गैर निष्पादित सम्पत्ति बन जाती है।
7. अन्य देशों में मंदी, अन्य देशों में बकाया धन राशि का भुगतान न करना, प्रतिकूल विनिमय दर कम्पनियों के संचालन और उनकी ऋण भुगतान क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
8. यदि वर्षा कम मात्रा में होती है या खराब प्राकृतिक परिस्थितियां होती है तो किसानों को नुकसान होता है परिणामस्वरूप वे बैंकों का ऋण समय से नहीं चुका पाते हैं। इसके अलावा भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाऐं भी फसलों एवं उद्योगों को नुकसान पहुंचाती है।

उद्देश्य

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की लाभदायकता पर गैर निष्पादित सम्पत्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कुल अग्रिमों और गैर निष्पादित सम्पत्तियों के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

वर्तमान शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक समंको पर आधारित है जिसके लिये व्यापक साहित्य सर्वेक्षण किया गया एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित वार्षिक वित्तीय विवरणों द्वारा एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरणों द्वारा सन् 2009–10 से सन् 2019–20 तक के आंकड़े एकत्रित किये गये।

शोध की परिकल्पनाए

1. **H_{O1}** स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सकल लाभ पर सकल गैर निष्पादित सम्पत्तियों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
2. **H_{O2}** स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कुल अग्रिम और सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति के मध्य कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है।

समंक विश्लेषण

H_{01} स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सकल लाभ पर सकल गैर निष्पादित सम्पत्तियों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

तालिका 1: सकल लाभ एवं सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति की राशि

(करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	सकल लाभ	सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति
2009-10	13,926.08	19,534.89
2010-11	14,954.23	25,326.29
2011-12	18,483.31	39,676.46
2012-13	19,950.89	51,189.39
2013-14	16,173.89	61,605.35
2014-15	19,313.96	56,725.34
2015-16	13,774.06	98,172.80
2016-17	14,855.16	112,342.99
2017-18	-15,528.24	223,427.46
2018-19	1,607.48	172,750.36
2019-20	25,062.76	149,091.85

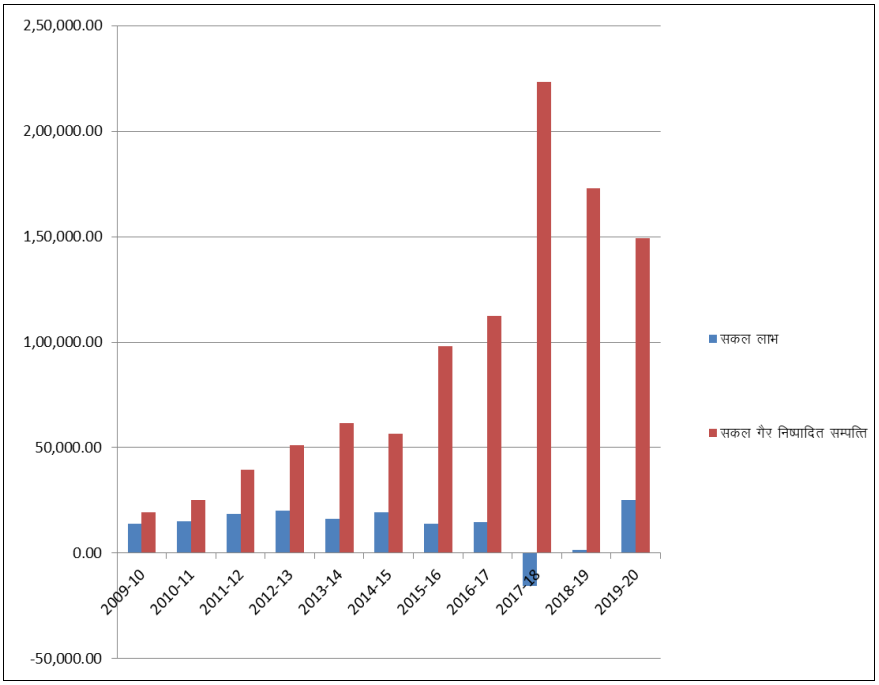

ग्राफ 1: सकल लाभ एवं सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति की राशि

तालिका 2

सह–सम्बन्ध गुणांक		
	सकल लाभ	**सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति**
सकल लाभ	1	.0ण686
सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति	.0ण686	1

उपरोक्त तालिका स्वतंत्र चर, सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति और आश्रित चर, सकल लाभ के मध्य सहसंबंध को दर्शाते हुए सह सम्बन्ध आव्यूह को प्रदर्शित करती है। सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति और सकल लाभ के मध्य सह सम्बन्ध का मान –0.686 है जो कि दोनों के मध्य ऋणात्मक सह सम्बन्ध को दर्शाता है।

तालिका 3

Descriptive Statistics			
Gross Profit		**Gross NPA**	
Mean	12961.23455	Mean	91803.925
Standard Deviation	11073.31158	Standard Deviation	66160.99

उपरोक्त तालिका स्वतंत्र चर, सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति और आश्रित चर, सकल लाभ के माध्यमान या समान्तर माध्य को दर्शाती है। यह तालिका सभी चरों के मानक विचलन को भी दर्शाती है।

तालिका 4

MODEL SUMMARY	
Regression Statistics	
R	(-)0.686
R Square	0.470
Adjusted R Square	0.412
Standard Error	8493.357
Observations	11

a. Predictors: (Constant), GNPA
b. Dependent Variable: Gross Profit

उपरोक्त तालिका में R square का मान 0.470 है जो यह इंगित करता है कि स्वतंत्र चर, सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति एवं आश्रित चर सकल लाभ के विचरण की लगभग 47ः से व्याख्या करता है। इस स्थिति में समायोजित R square यह दर्शाता है कि निर्भर चर की परिवर्तनशीलता का 47ः मॉडल द्वारा ध्यान में रखा जाता है जैसा कि आर वर्ग और समायोजित आर वर्ग के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है इसका मतलब यह है कि इस मॉडल में कोई भी स्वतंत्र चर बिना मतलब का नहीं है।

तालिका 5

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	576948233.1	576948233.1	7.998	0.020
Residual	9	649234060.3	72137117.81		
Total	10	1226182293			

a. Dependent Variable: Gross Profit
b. Predictors: (Constant), Gross NPA

एक्सेल की एनोवा तालिका में, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा महत्वता का F मान है। यह समग्र महत्व के एफ परीक्षण के लिये पी.मान है। उपरोक्त तालिका में थ् का परिकलित मान 7.998 है जो महत्वता के 0.020 स्तर पर सार्थक है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रतीपगमन विश्लेषण के लिये एक अच्छा मॉडल फिट है।

तलिका 6

Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	23500.92074	4521.849399	5.197	0.000
Gross NPA	-0.11480649	0.040595454	-2.828	0.020

a. Dependent Variable: Gross Profit

गुणांक तालिका से प्राप्त ''टी'' का मान –2.828 है जो महत्वता के स्तर 0.020 पर सार्थक है। तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि टी टेस्ट के लिये P का मान 0.05 से कम है जिसका अर्थ है कि सकल एन.पी.ए. का सकल लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। उपरोक्त तालिका अमानकीकृत गुणांक और मानकीकृत गुणांक भी दिखाती है अमानकीकृत गुणांक यह बताता है कि स्वतंत्र चर में एक इकाई की वृद्धि से आश्रित चर में भी ईकाई की वृद्धि होगी। मानकीकृत गुणांक यह बताता है कि स्वतंत्र चर में एक मानक विचलन वृद्धि से आश्रित चर में एक मानक विचलन वृद्धि होगी।

इस तालिका के आधार पर, प्रतीपगमन रेखा का समीकरण है –
23500.921-0.115 GNPA

H_{O2} कुल अग्रिम और सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

तालिका 7: कुल अग्रिम और सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति की राशि

वर्ष	कुल अग्रिम	सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति
2009-10	631914.15	19534.89
2010-11	756719.45	25326.29
2011-12	867578.89	39676.46
2012-13	1045616.55	51189.39
2013-14	1209828.72	61605.35
2014-15	1300026.39	56725.34
2015-16	1463700.42	98172.80
2016-17	1571078.38	112342.99
2017-18	1934880.19	223427.46
2018-19	2185876.92	172750.36
2019-20	2325289.56	149091.85

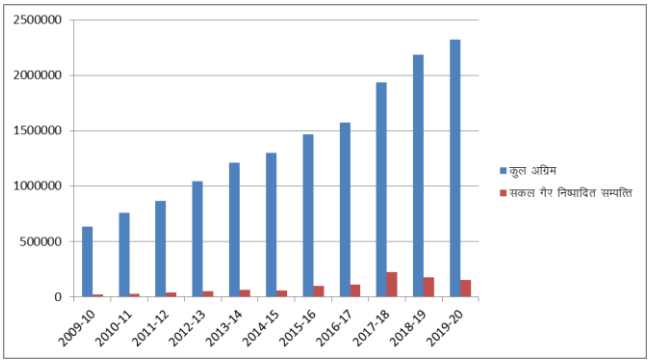

ग्राफ 2: कुल अग्रिम और सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति की राशि

तालिका 8

	Correlation	
	TotalAdvances	**Gross NPA**
TotalAdvances	1	0.903
Gross NPA	0.903	1

उपरोक्त तालिका स्वतंत्र चर, कुल अग्रिम एंव आश्रित चर, सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति के मध्य सह सम्बन्ध को दर्शाती है। कुल अग्रिम और सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति के मध्य सह सम्बन्ध का मान 0.903 है जो कि दोनो चरों के मध्य उच्च धनात्मक सह सम्बन्ध को दर्शाता है।

तालिका 9

Descriptive Statistics			
TotalAdvances		**Gross NPA**	
Mean	1390228.146	Mean	91803.925
Standard Deviation	570186.0007	Standard Deviation	66160.99

उपरोक्त तालिका स्वतंत्र चर, कुल अग्रिम और आश्रित चर, सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति के माध्य मान या समान्तर माध्य और मानक विचलन को दर्शाती है।

तालिका 10

Model summary

Regression Statistics	
R	0.902907541
R Square	0.815242027
Adjusted R Square	0.794713363
Standard Error	29976.59735
Observations	11

a. Predictors: (Constant), TotalAdvances

उपरोक्त तालिका R (सह सम्बन्ध) और R^2 के मान को दर्शाती है। R का मान स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के मध्य सह सम्बन्ध को दर्शाता है जो कि गणना के द्वारा 0.903 प्राप्त हुआ है R^2 का मान 0.815 है जो यह दर्शाता है कि स्वतंत्र चर (कुल अग्रिम) आश्रित चर (सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति) के विचरण की लगभग 81.5% से व्याख्या कर रहा है। इस स्थिति में समायोजित R^2यह दर्शाता है कि आश्रित चर की परिवर्तनशीलता का 81.5% मॉडल द्वारा ध्यान में रखा जाता है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि आर वर्ग और समायोजित आर वर्ग में अंतर बहुत अधिक नहीं है इसका तात्पर्य यह है कि यह मॉडल एक अच्छा मॉडल है जिसमें सभी स्वतंत्र चर महत्वपूर्ण है।

तालिका 11

ANOVA

	D f	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	35685398410	35685398410	39.712	0.000
Residual	9	8087367499	898596388.8		
Total	10	43772765909			
a. Dependent Variable: Gross NPA					
b. Predictors: (Constant), TotalAdvances					

उपरोक्त तालिका में F का परिकलित मान 39.712 है जो महत्वता के .000 स्तर पर सार्थक है। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रतीपगमन विश्लेषण की दृष्टि से एक अच्छा मॉडल फिट है।

तालिका 12

Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	-53847.5209	24817.13888	2.169771509	0.058135
TotalAdvances	0.104768017	0.016625158	6.301775689	0.000141

a. Dependent Variable: Gross NPA

गुणांक तालिका से प्राप्त टी का मान 6.302 है जो महत्वता के 0. 000 स्तर पर सार्थक है तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि टी टेस्ट के लिये P का मान 0.05 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। जिसका अर्थ है कि कुल अग्रिमों एवं सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति के मध्य महत्वपूर्ण संबंध है। उपरोक्त तालिका अमानकीकृत गुणांक और मानकीकृत गुणांक को भी दर्शाती है। अमानकीकृत गुणांक यह बताता है कि स्वतंत्र चर में एक इकाई की बृद्धि से आश्रित चर में भी एक इकाई की वृद्धि सम्भव है। मानकीकृत गुणांक यह बताता है कि स्वतंत्र चर में एक मानक विलचन की बृद्धि से आश्रित चर में भी एक मानक विचलन की वृद्धि होगी।

इस तालिका के आधार पर प्रतीपगमन रेखा का समीकरण है –

$$-53847.521 + 0.105 \text{ TA}$$

निष्कर्ष

बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण कडी का कार्य करता है। यदि हमें देश का आर्थिक विकास करना है तो उसके लिये आवश्यक है कि बैंको का भी यथा सम्भव विकास हो। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भारत की एक मुख्य बैंक है इसने पिछले कई दशकों से, भारत की बैंकिंग प्रणाली में कई उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की है।किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये गैर निष्पादित सम्पत्ति एक अपरिहार्य बोझ के रूप में होती है इसलिये किसी भी खाते को गैर निष्पादित सम्पत्ति बनने से रोकने के लिये इसकी नियमित रूप से निगरानी करने की आवश्यकता है। शोधार्थी द्वारा विभिन्न साहित्य और अन्य अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर यह

निष्कर्ष निकाला गया है कि गैर निष्पादित सम्पत्तियों की समस्या का हल उनके उचित प्रबंधन एवं उन्हें एक निश्चित स्तर तक नियंत्रित करने से ही निकाला जा सकता है।

वर्तमान अध्ययन में पिछले 11 वर्षो अर्थात् 2009–10 से 2019–20 तक की अवधि शामिल है। शोधार्थी ने अध्ययन के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति एवं गैर निष्पादित सम्पत्ति से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट (ANoVA), F टेस्ट और सह–सम्बन्ध गुणांक, रेखीय प्रतीपगमन विश्लेषण, तकनीकों का उपयोग किया है।परिकल्पनाओं के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सकल लाभ पर सकल गैर निष्पादित सम्पत्तियों का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है अर्थात सकल गैर निष्पादित सम्पत्तियों में वृद्धि होने के साथ सकल लाभ कम होने लगता है।इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कुल अग्रिमों एवं सकल गैर निष्पादित सम्पत्तियों में धनात्मक संबंध है अर्थात कुल अग्रिमों की राशि में वृद्धि होती है तो गैर निष्पादित सम्पत्तियों में भी वृद्धि होती है।विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि गैर निष्पादित सम्पत्तियों में वृद्धि का सबसे बड़ा एवं गम्भीर कारक जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले कर्जदार (पसनिस कमनिजमते) हैं। इनके पास किश्त चुकाने हेतु रकम तो होती है परन्तु फिर भी ये जानबूझकर बैंक की किश्त का भुगतान नहीं करते हैं। कभी –कभी ऐसे मामलों में बैंक के कर्मचारी भी इनके साथ शामिल होते है। ऐसे मामलों में कई बार इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। बैंको को ऐसे मामलों में उस डिफॉल्टर एवं कर्मचारी दोनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करना चाहिये। जिससे अन्य कर्जदारों को भी इससे सबक मिल सकें।

गैर निष्पादित सम्पत्तियों से होने वाली समस्याऐं

1. बैकों की लाभदायकता में कमी
2. तरलता में कमी
3. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान
4. प्रति अंश आय में गिरावट आती है
5. ब्याज आय में कमी
6. बैंक में उच्च गैर निष्पादित सम्पत्ति होने पर कर्मचारियों की उत्पादकता एवं कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

गैर निष्पादित सम्पत्तियों को कम करने हेतु सुझाव

1. बैंकों को उधारकर्ता का चयन करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिये। इसके लिये बैंक को उधारकर्ता की साख के बारे में गहन जांच करनी चाहिये एवं उनके सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करनी चाहिये।
2. जो उधारकर्ता अपनी उधार राशि का भुगतान बैंकों को नहीं करते हैं उनके नाम उधार राशि सहित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने चाहिये। समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित होने से यह उन उधारकर्ताओं की गरिमा को प्रभावित करेगा।
3. बकाया ऋणों की प्रभावी वसूली की दिशा में सरकार को कुछ नये कानून पारित करना चाहिये। कानून पारित करके वसूली अधिकरण, वसूली विभाग, लोक अदालत आदि को अधिक अधिकार दिये जाना चाहिये
4. बैंको को ऐसे उधारकर्ताओं से नियमित बातचीत करते रहना चाहिये जो ब्याज या मूलधन के भुगतान में अनियमितता को दर्शा रहे हैं और जिनकी भविष्य में गैर निष्पादित सम्पत्ति बनने की सम्भावना है।
5. गैर निष्पादित सम्पत्तियों की वूसली के लिये बैंको को अपने कर्मचारियों को उचित और नियमित प्रशिक्षण देना चाहिये यदि ऐसे काम में किसी नये कर्मचारी को लगाया जाए तो उसे किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित कर्मचारी के साथ काम करवाना चाहिये।

शोध की कमियां

प्रस्तुत शोध पत्र पूर्ण रूप से द्वितीयक समंको पर आधारित है। शोधार्थी ने समंको का विश्लेषण पूर्ण रूप से बैकों के 11 वर्षो के वार्षिक विवरणों के आधार पर ही किया है।

भावी शोध की सम्भावनाए

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को ही अध्ययन के आधार के रूप में लिया गया है, जबकि गैर निष्पादित सम्पत्ति की समस्या अन्य बैंको में भी देखने को मिलती है। अतः भविष्य में इसमें अन्य बैंको को भी शामिल किया जा सकता है।
2. देश की जी.डी.पी. और आर्थिक विकास पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की गैर निष्पादित सम्पत्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. वैद्य शिवानी] "Non PerformingAssets :A comparative Study on State Bank of IndiaAnd Punjab National Bank"Asia Pacific Journal of Research, 2016, 46(1).
2. डॉ. डी गणेशनएसांथनाकृष्णन आर"Non PerformingAssets :A Study of State Bank of India"Asia Pacific Journal of Research, 2013, 10(1).
3. चौधरी fodkl "Performance evaluation of public Sector Banks in India." Shri Krishna International ResearchAnd Educational Consortium, 1(1), 1-17.
4. जत्ना रेणु " Impact of NPA's on Profitability of Bank" Indian Journal ofAccounting,2009:39(2):21-27.
5. Banerjee B, DanAK. "Management of Non-performingAdvances in the Public Sector Banks in India", New Trends in Corporate Reporting (Edited Book), RBSA Publishers, Jaipur, 2006, 115-137.
6. अजीत कुमार, द इम्पेक्ट ऑफ एन.पी.एज ऑन द प्राफिटेबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पटना बिहार, प्रकाशित शोध ग्रंथ, वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
7. रावल मनीष भास्कर, भाई (2014) एन एनलिटिकल स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इण्डिया प्रकाशित शोध ग्रंथ वाणिज्य विभाग, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, 2014
8. Singh Rajbahadur Vivek (2016)A Study of Non-PerformingAssets of Commercial BanksAnd it's recovery in IndiaAnnual Research Journal of SCMS, Pune, 2016, 4.
9. Banerjee B, DanAK. "Management of Non-performingAdvances in the Public Sector Banks in India", New Trends in Corporate Reporting (Edited Book), RBSA Publishers, Jaipur, 2006¸115-137
10. Jatna, Renu. "Impact of NPAs on Profitability of Banks", Indian Journal ofAccounting,2009:39(2):21-27.
11. रावल मनीष भास्कर, भाई (2014) एन एनलिटिकल स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इण्डिया प्रकाशित शोध ग्रंथ वाणिज्य विभाग, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, 2014
12. अजीत कुमार, द इम्पेक्ट ऑफ एन.पी.एज ऑन द प्राफिटेबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पटना बिहार, प्रकाशित शोध ग्रंथ, वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
13. Singh Rajbahadur Vivek.A Study of Non-PerformingAssets of Commercial BanksAnd it's recovery in IndiaAnnual Research Journal of SCMS, Pune, 2016, (4).